पुल ढहने की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से एक रिट याचिका पर प्रत्युत्तर मांगा है, जो **राज्य में बार-बार** पुल ढहने की घटनाओं को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बिहार में **पुलों के उच्चस्तरीय संरचनात्मक ऑडिट** के साथ-साथ प्राण रक्षा के लिये कमज़ोर निर्माणों (प्रमुखतः पुल) को इरादतन ध्वस्त करने अथवा उनकी मरम्मत करने के लिये **दायर की गई याचिका** के जवाब में नोटिस जारी किया।
- याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिये एक नीति या प्रणाली स्थापित करे, जो **राष्ट्रीय राजमार्गों और** केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिये **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** द्वारा विकसित तंत्र के समान हो।
    - उक्त संदर्भित नीति का फोकस **"सेंसर का उपयोग करके पुलों की वास्तविक समय पर स्थिति निगरानी की पहचान और कार्यान्वयन"** पर होना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-notice-on-collapsing-bridges